Topic no.36

आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक

अत्यावश्यक 50 विषय

प्रीलिम्स 2019 के लिए

क्यों अत्यावश्यक विषय श्रृंखला महत्वपूर्ण है?

2017 के प्रीलिम्स में, 50 अत्यावश्यक विषय श्रृंखला में 9 प्रश्न शामिल थे।

2018 की प्रारंभिक परीक्षा में, 40 अत्यावश्यक विषय श्रृंखला में 8 प्रश्न शामिल थे।

2019 के प्रीलिम्स में, ...

Telegram पर अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के लिए, हमारे चैनल @UpscPrepMate से जुड़ें

जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

पुस्तकें खरीदने के लिए

पर क्लिक करें

Whatsapp पर अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के लिए, अपना नाम और शहर Whatsapp नंबर पर भेजें

75978-40000

आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक (Economic freedom index)

आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक एक वार्षिक सूचकांक है जो दुनिया के विभिन्न देशों में आर्थिक स्वतंत्रता के स्तर को मापता है। सूचकांक 1995 में 'द हेरिटेज फाउंडेशन' और 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' द्वारा बनाया गया था। सूचकांक इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि "समाज की समृद्धि व्यक्तियों को अपने स्वयं के आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए दी गई आजादी का परिणाम है"।

आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के तहत रैंकिंग की प्रणाली

राष्ट्रों को उनके अंकों के अनुसार 5 श्रेणियों में स्थान दिया गया है - स्वतंत्र (100-80), ज्यादातर स्वतंत्र (79.9-70), मध्यम रूप से स्वतंत्र (69.9-60) ज्यादातर अस्वतंत्र (59.9-50) और विनियमित (49.9-40)।

आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के तहत भारत का प्रदर्शन

अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किए गए 2018 वार्षिक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट में 180 देशों के बीच भारत ने 130 वां स्थान (2017 की रिपोर्ट में 143 वां स्थान था) हासिल किया है।

हांगकांग ने लगातार चौथे वर्ष पहला स्थान हासिल किया है व दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः सिंगापुर और न्यूजीलैंड हैं। पाकिस्तान 131 वें स्थान पर है।